पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 15, अंक 1/2014

नागरिकों एवं जन प्रतिनिधियों के परस्पर सहयोग से शहरी सेवाओं में सुधार संभव

कट्स द्वारा जयपुर शहर में चलाई जा रही 'माई सिटी' परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत जयपुर नगर निगम के पार्षदगणों के साथ एक विचार विमर्श बैठक का आयोजन 17 फरवरी, 2014 को किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए उप महापौर मनीष पारीक ने कट्स द्वारा संचालित माई सिटी परियोजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह परियोजना नागरिकों की भागीदारी से स्थानीय निकायों की सेवाओं में सुधार करने में सफल साबित हुई है।

परियोजना के प्रथम चरण के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि परियोजना से आम जनता में निगम संबंधी जागरूकता का विस्तार हुआ है। शहर के पार्षदों ने परियोजना की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर लाभ उठाया है। परियोजना के दौरान उपलब्ध कराये गये मंच से नागरिकों द्वारा बताई गई जन समस्याओं की चर्चा एवं निराकरण करने में सहयोग मिला है, साथ ही जन प्रतिनिधियों ने भी उनके सामने आ रही समस्याओं को साझा किया। इससे नागरिकों एवं जन प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर सहयोग की भावना का विस्तार हुआ।

उक्त बैठक में भाग लेते हुए पार्षदों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए, साथ ही भविष्य में परियोजना की सफलता हेतु कई प्रकार के सुझाव भी दिए। बैठक में दस से अधिक पार्षदगणों तथा परियोजना की सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। बैठक का उद्देश्य माई सिटी परियोजना के उद्देश्यों एवं गतिविधियों को प्रतिभागियों से साझा करना साथ ही, स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधियों के साथ संबंधों को सुधारना था ताकि परियोजना का सही प्रकार से क्रियान्वयन किया जा सके। इसके अलावा सेवा आपूर्ति करने में जन प्रतिनिधियों के सामने आ रही समस्याओं को समझने में बैठक से सहायता मिली। सहयोगी स्वयं सेवी संस्थाओं ने वार्ड स्तर पर आ रही समस्याओं एवं अपेक्षित सहयोग के बारे में पार्षदगणों से चर्चा की। पार्षदगणों ने संस्थाओं को पूर्ण रूप से सहयोग करने हेतु आश्वस्त किया।

कट्स के प्रतिनिधि अमर दीप सिंह व ओम प्रकाश आर्य ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए पार्षदगणों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रश्नों एवं सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उक्त विचार विमर्श बैठक से स्थानीय निकायों के सामने आ रही समस्याओं एवं क्रियान्वयन को समझने में सहायता मिली।

जन सहभागिता से संभव है समस्याओं का इलाज

गली मोहल्लो से परेशान होने पर हमने भले ही अपना समय नगर निगम को कोसने में निकाल दिया हो, लेकिन जयपुर स्थित श्याम नगर निवासियों ने इसका इलाज खोज निकाला है। स्थानीय लोगों ने न्यू सांगानेर रोड़ के पास जनपथ पर सड़क के दोनों ओर चमचमाते हुए कचरा पात्र रखवाए हैं।

निगम से कई बार गुहार करने के बावजूद भी जब कचरे की समस्या हल नहीं हुई तो श्याम नगर विकास समिति के जरिए स्थानीय लोगों ने 20 कचरा पात्र स्वयं ही खरीदकर रखवा दिए हैं।

इन कचरा पात्रों को निगम के कचरा पात्रों की विशिष्टताओं के मुताबिक ही बनवाया गया है, ताकि इनका कचरा निगम के कॉम्पेक्टर वाहन से भी आसानी से डाला जा सके।

श्याम नगर विकास समिति के सचिव ओ.पी. अग्रवाल का कहना है कि समिति ने अपने क्षेत्र में सफाई के लिए यह कदम उठाया है। यदि सरकारें विकास समितियों को सशक्त करें तो शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। आंध्रप्रदेश में सरकार ने ऐसा मॉडल विकसित किया हुआ है।

समिति ने यह एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तरह जन सहभागिता से हम सभी अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को स्वयं दूर कर नई मिसाल पेश कर सकते हैं।

इस अंक में...

- नहीं मिला फसल बीमा का फायदा 3
- भ्रष्टाचार के 'संरक्षण' में राजस्व विभाग अव्वल .. 5
- बन्द नहीं होंगी कोई भी योजनाएं 7
- विजिलेंस विंग बने तो रुके पानी चोरी 9
- बनेगा स्वास्थ्य नियामक आयोग 11

प्रधानमंत्री पद के लिए नरेन्द्र मोदी सबसे आगे

विधानसभा चुनावों का अनुसरण करते हुए लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान से बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। प्रदेश के 76 फीसदी लोगों ने इस पर अपनी मुहर लगाई है, वहीं 67 फीसदी लोग प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के नरेन्द्र मोदी को ही पसन्द करते हैं। यह तथ्य कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) द्वारा हाल ही राजस्थान में कराए गए 'हालात सर्वे 2014' से सामने आया है।

हालांकि प्रदेश के 66 फीसदी लोग यह मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के उदय से राजनीति की दशा व दिशा में परिवर्तन आएगा अर्थात राजनीति व्यक्तिवाद से हट कर मुद्दों पर आधारित होने लगेगी।

यह सर्वेक्षण लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव व तदोपरान्त की स्थिति के आकलन व लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से राज्य के विभिन्न जिलों में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कार्यरत चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से किया गया।

संस्था द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व भी एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 64 फीसदी लोगों ने मोदी को पीएम पद के लिए पसंद किया था। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कराए गए नए सर्वेक्षण में तीन फीसदी अधिक लोगों की मोदी के प्रति आस्था बढ़ी है। राजस्थान के केवल 10 फीसदी लोगों ने आम आदमी पार्टी व इतने ही फीसदी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था जताई है। सर्वे के मुताबिक पीएम पद के लिए मात्र 16 फीसदी लोगों ने अरविन्द केजरीवाल तथा 10 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी को पसन्द किया है।

लोकसभा चुनाव में हालांकि आम आदमी पार्टी का असर राजस्थान में उतना नहीं है, फिर भी जितना है, उससे कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, प्रदेश के 62 फीसदी लोगों ने यह संभावना व्यक्त की है। प्रदेश के 47 फीसदी लोगों ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के राजनीति में प्रवेश को सही ठहराया है, जबकि इतने ही फीसदी लोग इसे सही नहीं मानते।

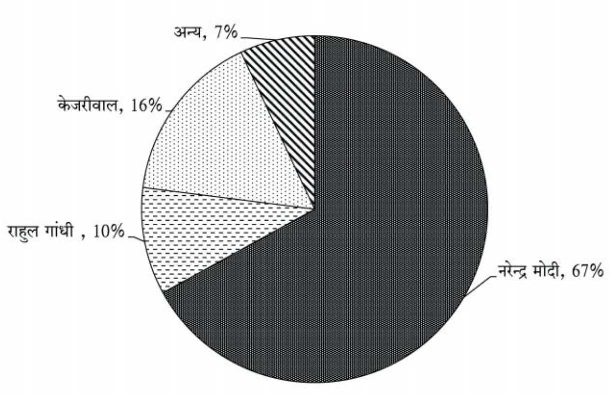

यह भी आया सामने

- *दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई, जिसे प्रदेश के 53 फीसदी लोगों ने सही नहीं माना, वहीं 72 फीसदी लोगों का कहना यह भी था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सहयोग से सरकार नहीं चला पाएगी। (यह सर्वे दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व करवाया गया था)*
- *साथ ही 45 फीसदी लोग भाजपा के सहयोग से सरकार बनाने के भी पक्ष में नहीं थे। हालांकि इतने ही फीसदी लोगों का यह भी विश्वास है कि आम आदमी पार्टी राजनीति में तीसरे मोर्चेके रूप में उभर सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा पानी बिजली की दरों में की गई कमी और छूट को राजस्थान के 68 फीसदी लोगों ने उचित बताया।*

जैसे, टोंक जिले के मुरलीधर शर्मा ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है 'आम आदमी पार्टी को यदि समाज व देश से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है तो राजनीति का मार्ग छोड़कर समाज सुधार का कार्य कर जागरूकता लानी चाहिए व भ्रष्टाचार के खिलाफ पैरवी करनी चाहिए।'

उपभोक्ता जन संवाद आयोजित

'कट्स' द्वारा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर 'फिक्स ऑवर फोन राइट्स' विषय पर जन संवाद आयोजित किया गया। संवाद के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से सिम खोने पर एफआईआर की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई तथा इस मुद्दे पर 'ट्राई' के साथ भी पैरवी की जाएगी।

कार्यक्रम में कट्स निदेशक जार्ज चेरियन ने सेवा प्रदाता कंपनियों और उपभोक्ता प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बताया कि मोबाइल फोन आज आम आदमी की जरूरत बन गया है। इसके माध्यम से बैंकिग सेवाएं, ई-कामर्स या सामाजिक सेवाओं का जुड़ाव भी होने लगा है। जन सवांद में सेवा प्रदाताओं जिनमें खास तौर पर बीएसएनएल, टाटा डोकोमो, एयरसेल, आईडिया आदि के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने अपनी कंपनियों से संबंधित विभिन्न सेवाओं, शर्तों, नियमों एवं उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर उपभोक्ता संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मोबाइल सेवाओं से सम्बन्धित आम उपभोक्ता की विभिन्न समस्याओं को उठाया और पूरे देश में फ्री रोमिंग की मांग भी की।

सही योजना उचित कदम! सुशासन का यह है धर्म !!

नहीं मिला फसल बीमा का फायदा

किसानों के लिए 2006 में शुरू हुई मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रदेश के किसानों को सही फायदा नहीं मिल पाया है। अभी खरीफ-2013 की फसल का मुआवजा बांटा जा रहा है। बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील में मेतवाला वैदर स्टेशन से जुड़े किसानों को उड़द की फसल में खराबी पर औसत रूप में मात्र 42 पैसे का मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि किसानों की हजारों रुपए की फसल नष्ट हुई है।

किसानों का सामूहिक बीमा होने से यहां 2101 किसानों के लिए 878 रुपए का मुआवजा आया है। करीब-करीब यही हाल राज्य के अन्य जिलों में है। किसानों के साथ यह क्रूर मजाक है। राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि वे इस योजना में सुधार के लिए केन्द्र सरकार से बात करेंगे।

(दै.भा., 30.01.14)

मौसम बीमा: किसानों की झोली खाली

प्रदेश के आधे से भी ज्यादा जिलों में हुई ओलावृष्टि से करोड़ों रुपए की फसलें बरबाद हो गई। लेकिन केन्द्र सरकार की मौसम आधारित बीमा योजना में भारी खामियां होने के कारण किसानों को कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। किसानों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने योजना को बनाया ही इस तरह है, जिससे किसानों की जेब कटे और कंपनियां मालामाल हों।

सरकार की खामियों के कारण बीमा कंपनियां 65 फीसदी से ज्यादा पैसा अपनी जेब में डाल रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों फसल खराबी पर किसानों को 40-40 पैसे मुआवजा देने वाली बीमा कंपनियों ने पिछले छह साल में 53 लाख 80 हजार किसानों से 1074 करोड़ रुपए कमाए हैं। बीमा कंपनियां किसानों से मिले प्रीमियम से भी कम राशि का क्लेम दे रही हैं।

(दै.भा., 28.02.14)

करोड़ों खर्च, नतीजा सिफर

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट था। लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 32 में से 19 जिलों में जल गुणवत्ता जांचने का आंकड़ा लक्ष्य के मुकाबले एक फीसदी को भी पार नहीं कर पाया। पांच फीसदी से ज्यादा का आंकड़ा सिर्फ दो जिले ही प्राप्त कर पाए हैं, जिसमें से बाड़मेर में 7.19 और हनुमानगढ़ में 9.19 फीसदी उपलब्धि अर्जित की है।

यह कार्यक्रम वर्ष 2008 से चल रहा है और इसके लिए 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। अब तक करीब 900 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं, लेकिन 19 जिलों में काम ही नहीं हुआ। पेयजल स्त्रोतों की साल में तीन बार जांच का प्रावधान था परन्तु अधिकतर जिलों में ऐसा नहीं किया गया। विभागीय उदासीनता के चलते फील्ड टेस्ट किट में काम आने वाला रसायन भी सूख गया। *(रा.प., 19.01.14)*

पर्यावरण सुधार, जमा राशि नहीं हुई खर्च

पर्यावरण सुधार के नाम पर खान विभाग डेढ़ साल में खान मालिकों से सौ करोड़ रुपए से भी ज्यादा वसूल चुका है, लेकिन पर्यावरण सुधार पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। इतना ही नहीं खान मालिकों से लाखों रुपए खर्च कर तैयार कराए पर्यावरण सुधार के प्लान अभी भी कलेक्ट्रेट के दफ्तरों में धूल फांक रहे हैं।

बड़े पैमाने पर हो रहे खनन से राज्य के बिगड़ते पर्यावरण में सुधार के लिए खान विभाग ने राज्य के पांच हैक्टेयर से छोटे खान क्षेत्रों को क्लस्टर में बांट कर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कराए गए थे। राज्य भर में करीब 900 क्लस्टर क्षेत्रवार बनाए गए थे। तैयार प्लान को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी से मंजूर करा कर क्षेत्र में पर्यावरण सुधार कार्य कराए जाने थे। खान विभाग के अधिकारियों ने प्लान पास कराने के बाद कलेक्टर कार्यालयों में पेश कर दिए पर कई बैठकें होने के बावजूद एक भी प्लान अभी तक मंजूर नहीं हुआ। *(रा.प., 26.01.14)*

मनरेगा रोजगार दिवसों में आई गिरावट

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में परिवारों को रोजगार मिलने के दिन लगातार घट रहे हैं। वर्ष 2013-14 के फरवरी माह तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार रोजगार दिवस 39 ही रह गए हैं। जबकि 2010-11 में यह आंकड़ा 52 का था।

योजना के तहत होने वाले कार्यों में इस साल हर सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। महिलाओं के कार्यदिवस का मामला हो या फिर 100 दिन कार्य पूरा करने वाले परिवारों की बात हो, यह आंकड़ा पिछले चार सालों में लगातार गिरता जा रहा है। पंचायतें भी राशि खर्च करने के मामले में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही। *(रा.प., 11.03.14)*

खाद्य सुरक्षा योजना में घालमेल

विधानसभा चुनाव से पहले लागू की गई खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश के पांच जिलों में आबादी से भी ज्यादा लोग चयनित कर दिए गए। इन जिलों में 84 लाख लोगों के नाम योजना में ज्यादा जोड़े गए हैं। अनेक अपात्र लोगों का भी इसमें चयन हो गया। हाल ही योजना की समीक्षा में यह गड़बड़ी सामने आई है।

दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, बांरा और सवाई माधोपुर जिलों में यह गड़बड़ी सामने आई है। जल्दबाजी में तैयार की गई कई सूचियों में जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद चयनित लोगों की वास्तविकता का पता लगाया जाएगा और वास्तविक जरूरतमंदों के नए सिरे से नाम भी जोड़े जाएंगे। *(दै.भा., 10.03.14)*

खादी के लिए दिए, खर्चे कहीं और

राजस्थान खादी एवं ग्रामाद्योग बोर्ड ने टूल किट खरीदने के लिए सब्सिडी के तौर पर प्रदेश के करीब 25 हजार बुनकरों को 12 करोड़ 50 लाख रुपए बांट दिए, लेकिन विभाग को ही पता नहीं है कि बुनकरों ने इस राशि का किया क्या? यहां तक कि जिनको यह राशि दी गई उनको खुद को पता नहीं कि इन रुपयों का करना क्या था। नतीजतन, सभी ने अपने हिसाब से राशि का उपयोग कर लिया।

पिछली सरकार ने बोर्ड के जरिए राशि वितरण की योजना की बजट में घोषणा की थी, जिसके बाद बोर्ड ने अपनी पंजीकृत खादी संस्थाओं से उनके यहां सक्रिय बुनकरों और कातिनों के नाम मांगे थे। प्रदेश के करीब 300 संस्थाओं ने नाम भेज दिए। उन्हें पांच-पांच हजार के चैक भिजवा दिए गए। लेकिन अब विभाग को पता नहीं है कि उन्होंने इस राशि का क्या किया।

(दै.भा., 05.02.14)

स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना में घोटाला

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार देने के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति-जनजाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से निजी कंपनियों से प्रशिक्षण दिलाने के मामले में हुई उच्च स्तरीय लेखा जांच में ज्यादा भुगतान और कई अनियमितताएं सामने आई हैं।

राजस्थान पत्रिका ने 'प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों का घोटाला' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर यह मामला उठाया था। मामले को जनवरी-मार्च 2013 के पांचवा स्तम्भ में भी प्रकाशित किया गया था।

विशेष लेखा जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 15 जिलों में बेंगलूरु की टेली सोल्यूशन के माध्यम से एससी-एसटी के छात्रों को प्रशिक्षण व रोजगार देने के उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। स्थिति यह रही कि इसमें 50 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से जोड़ने का उद्देश्य तक पूरा नहीं हो सका। रिपोर्ट में सामने आया कि निजी कंपनी के पार्टनरों ने प्रशिक्षणार्थियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्शाकर भुगतान उठा लिया व निगम अधिकारियों ने भी बिना जांच भुगतान कर दिया। *(रा.प., 23.03.14)*

पंचायती राज संस्थाओं में गबन

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं गबन-घोटालों की नई जगह बन गई है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, 2012 तक प्रदेश की पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 21 करोड़ 55 लाख रुपए का गबन हुआ है।

प्रदेश की 260 ग्राम पंचायतों में 50 हजार से भी ज्यादा और 6591 ग्राम पंचायतों में 50 हजार रुपए तक के गबन के मामले सामने आए हैं। 458 पंचायत समितियों और दो जिला परिषदों में भी गबन के मामले मिले हैं। सबसे ज्यादा मामले ग्राम पंचायतों में हैं। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में भी आठ करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी पकड़ी गई है। *(रा.प., 22.02.14)*

खर्च करने में भी कछुआ चाल

प्रदेश की अगली वार्षिक योजना 2014-15 करीब 46 हजार करोड़ रुपए की हो सकती है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, हालांकि चालू वित्त वर्ष 2013-14 की योजना में हो रहा खर्च कछुआ चाल को भी मात कर रहा है। आयोजना विभाग की 5 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसम्बर तक चालू वार्षिक योजना की 63.5 फीसदी राशि ही खर्च हो पाई है।

प्रदेश की पिछली सरकार द्वारा बनाई गई 40 हजार 500 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना में 9 महीने बीतने पर भी मात्र 25 हजार 728 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके हैं। अब सभी विभाग आनन-फानन में राशि खर्च करने में जुटे हैं। उनके पास करीब 36.5 फीसदी राशि को खर्च करने के लिए सिर्फ 3 महीने शेष है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लगने और नई सरकार गठित होने के कारण राशि कम खर्च हो पाई है। *(रा.प., 06.02.14)*

लेटलतीफी से लगा करोड़ों का फटका

वर्ष 2008-09 में कालीसिंध, छबड़ा व रामगढ़ बिजलीघरों में काम की शुरूआत हो गई थी। बाद में लेटलतीफी को लेकर कई बार राजनीति भी गर्माई, लेकिन तत्कालीन सरकार की ढिलाई के चलते परियोजना की लागत बढ़ती चली गई।

राज्यसभा सांसद ज्ञानप्रकाश पिलानिया के सवाल के जवाब में सामने आया कि अकेले कालीसिंध परियोजना की लागत ही 4600 करोड़ रुपए से बढ़ कर 7723 करोड़ रुपए पहुंच गई है। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की लापरवाही से बिजलीघरों के निर्माण में हो रही देरी ने आम उपभोक्ता पर बिजली की मार का संकट खड़ा कर दिया है। 1500 मेगावाट क्षमता के इन बिजलीघरों के निर्माण में अपनी तय सीमा से करीब ढ़ाई वर्ष ज्यादा बीतने के बावजूद शुरू नहीं हुए। इससे बिजलीघरों की निर्धारित लागत में 4200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। *(रा.प., 21.02.14)*

नहीं महकी किसानों की बगिया

पैसा होने के बावजूद उद्यान निदेशालय के अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते राष्ट्रीय बागवानी मिशन में तय लक्ष्यों के अनुरूप काम नहीं हुआ। नतीजतन, सरकारी राशि होते हुए भी किसानों की बगिया ढंग से महक नहीं सकी।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रदेश में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन सरकार पिछले नौ माह में केवल 21 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई।

योजना के तहत राज्य के 24 जिलों में फल, सब्जी, मसाला, फूल, औषधीय पौधे लगाने, मधुमक्खी पालन, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कार्यों के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को पूरी सहायता नहीं मिल पाई। *(रा.प., 03.03.14)*

सरकार ने उठा लिया बेरोजगारी भत्ता

सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के स्थान पर उनके लिए स्वीकृत किए गए भत्ते को ही उठा लिया। ऐसा प्रदेश के कई रोजगार कार्यालयों में हुआ है। अकेले बीकानेर में करीब 1800 बेरोजगार युवक-युवतियों को पिछले सात माह से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार है। इन्हें भत्ते की अन्तिम किस्त जुलाई, 2013 को मिली थी। इसके बाद से ही सरकार भत्ता देने के लिए टालमटोल कर रही है।

बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के तहत स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों को प्रति माह 500 रुपए तथा अपाहिज स्नातक को प्रति माह 600 रुपए देने का प्रावधान है। अब विधानसभा चुनाव के बाद बजट का अभाव बताकर भत्ते के भुगतान के मामले को ही टाल दिया है। *(रा.प., 13.03.14)*

करोड़ों की दवाएं हुई खराब

निःशुल्क दवा योजना ने निश्चित ही आमजन को बड़ी राहत दी, लेकिन योजना को लागू करने में मेनेजमेंट के स्तर पर अफसरों की लापरवाही भी खूब रही। दवा और मेडिकल आइटम्स की संख्या बढाने के साथ ही एक ओर तो इनकी कम सप्लाई ने मरीजों को परेशान रखा, वहीं अब यह भी सामने आया है कि कई दवाएं तो अस्पताल और मरीजों तक पहुंचने से पहले ही अवधिपार हो गई। संबंधित अफसरों ने कुछ दवा कंपनियों से एक साथ दो साल का माल खरीद लिया, जबकि इन्हें त्रैमासिक या छमाही पर खरीदना चाहिए था।

दवाओं की खरीद से पहले उनकी मांग और सप्लाई का सही आकलन करने में कहां चूक रही? क्या दवाओं की मांग के बावजूद दवाएं गोदाम से बाहर नहीं निकली? क्योंकि अक्सर सप्लाई की कमी को लेकर सवाल उठते रहे। सवाल यह भी है कि क्या जानबूझ कर कुछ दवा कंपनियों से बिना आकलन जरूरत से ज्यादा दवाएं खरीदी गई? *(दै.भा., 26.01.14)*

भ्रष्टाचार के 'संरक्षण' में राजस्व विभाग अव्वल

भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे अपने कर्मचारियों-अधिकारियों को संरक्षण देने में राजस्व विभाग सबसे आगे है। विभाग में ऐसे 41 कर्मिकों की अभियोजन स्वीकृति अटका रखी है जिन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पकड़ा था। यही नहीं, 15 तहसीलदारों के खिलाफ तो अभियोजन स्वीकृति देने से ही मना कर दिया। इसी कारण एसीबी को भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में पसीने आ रहे हैं।

एसीबी ने पांच सालों के दौरान ट्रैप और पद के दुरुपयोग के मामले में पकड़े गए 20 कर्मचारियों व अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी। इनमें 3 मामले लिपिक और बाकी तहसीलदार व नायक तहसीलदार के हैं। राजस्व मंडल ने इनमें से 15 तहसीलदारों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। अभियोजन स्वीकृति से मना करने पर अक्सर कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाती है, लेकिन विभाग ने यह भी नहीं की। *(रा.प., 24.02.14)*

भारत में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार

अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में न्याय पालिका समेत सरकार के हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट अर्थात कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसेज में यह कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार हालांकि अधिकारिक स्तर पर भ्रष्टाचार होने पर कानून अपराधिक दंड देता है, लेकिन भारत सरकार ने कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है और अधिकारी छूट का फायदा उठा कर भ्रष्ट कामों में लिप्त हो जाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के हर स्तर पर भ्रष्टाचार मौजूद है। सीबीआई ने जनवरी से नवंबर माह के बीच 583 मामले दर्ज किए। गैर सरकारी संगठनों ने पाया कि घूस आमतौर पर जल्दी काम करवाने के लिए दी गई, इनमें पुलिस, सुरक्षा, स्कूल दाखिला, पानी की आपूर्ति व सरकारी मदद जैसे काम प्रमुख थे। गरीबी हटाने और रोजगार दिलाने के कई सरकारी कार्यक्रम खराब क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित हुए हैं। *(न.दु., 01.03.14)*

बिना रिश्वत काम नहीं, अब भुगतो सजा

सरकारी विभागों में बिलों के भुगतान की एवज में हो रही कमीशनखोरी पर भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकारी विभागों में बकाया बिलों के भुगतान की एवज में कर्मचारियों द्वारा बिना रिश्वत लिए काम नहीं करने की नई प्रवृत्ति पनप रही है। ऐसी स्थिति में देश, राज्य व लोकहित को ध्यान में रखते हुए दोषी कर्मचारी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

न्यायाधीश ने यह टिप्पणी देते हुए एक ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में पांच सौ रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए बीएसएनएल के लेखाधिकारी हरी सिंह मीणा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। हैरानी वाली बात यह है कि मीणा की मासिक तनख्वाह एक लाख रुपए से ज्यादा है, फिर भी उनका मन 500 रुपए की घूस पर डोल गया।

(रा.प., 15.02.16, 16.02.14)

लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

पिछले 46 साल से बहुप्रतिक्षित लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। विधेयक को राज्यसभा ने 17 दिसम्बर को पारित किया था और 18 दिसम्बर को यह लोकसभा में पारित हो गया था। इसके बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। विधेयक पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए हैं। सरकार ने भी लोकपाल के गठन की कवायद तेज कर दी है।

विधेयक में केन्द्र के स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त के गठन का प्रावधान है। प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में रखा गया है। हर श्रेणी के लोकसेवकों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। ईमानदार लोकसेवकों को पूरा संरक्षण प्रदान किया गया है। लोकपाल को संदर्भित मामलों में सीबीआई सहित किसी भी जांच एजेंसी को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.01.14, 19.01.14)

भ्रष्टाचार के मामले 13 फीसदी बढ़े

रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामले वैश्विक स्तर पर 2011 के मुकाबले 13 फीसदी बढ़ गए हैं। इसमें इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र सूची सबसे ऊपर है। इसके बाद सरकारी कामकाज का स्थान आता है। यह पीडब्लूसी द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है। बहुराष्ट्रीय लेखा कंपनी के मुताबिक रिश्वत और भ्रष्टाचार की इस साल भी आर्थिक अपराध में प्रमुख भूमिका बनी रहेगी। पीडब्लूसी ने अपने 2014 के वैश्विक आर्थिक अपराध सर्वेक्षण में कहा है कि हर क्षेत्र में रिश्वत और भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

27 फीसदी लोगों ने कहा है कि वे आर्थिक अपराध के शिकार हुए है। गबन और खरीद में धोखाधड़ी के बाद यह तीसरा सबसे अधिक होने वाला अपराध है। इसके अलावा रिश्वत और भ्रष्टाचार जो 2011 में 24 फीसदी पर था उसमें 13 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। पीडब्लूसी ने कहा कि जिन कंपनियों को अक्सर रिश्वत और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा उन्हें 50 लाख डालर से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है।

(न.दु., 30.02.14)

रिश्वत देने वाली कंपनियां दंडित हों

संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि देश में कोई भी भारतीय या विदेशी कंपनी से जुड़ा कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देने का दोषी पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। विधि एवं कार्मिक संबंधी संसद की स्थाई समिति ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून संशोधन विधेयक 2013 पर अपनी रिपोर्ट में ऐसे रिटायर्ड नौकरशाहों को कुछ कवच प्रदान करने के कदम का समर्थन किया है, जिन पर सेवा में रहते कुछ गलत करने के आरोप लगे।

विधेयक के मुताबिक कोई भी कंपनी भारतीय हो या विदेशी लेकिन उसका कारोबार भारत में हो और चैरिटी सहित सेवाएं दे रही हो, उसके साथ संबद्ध किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने से रोकने के लिए जिम्मेदार होंगी। *(न.दु., 07.02.14)*

महिलाओं से मांगी गई रिश्वत

एक अध्ययन में दावा किया गया है कि बीते 12 महीनों में लोक सेवाएं प्राप्त करने के प्रयास में करीब 66 प्रतिशत महिलाओं से कम से कम एक बार रिश्वत मांगी गई। सीएमएस इंडियन करप्शन स्टडी अर्थात सीएमएस आईसीएस 2013 के नौवें दौर में महिलाओं के मौलिक और महत्वपूर्ण लोक सेवाएं प्राप्त करने के सम्बन्ध में विशेष रूप से गौर किया गया। इसमें खुलासा हुआ कि करीब 24 प्रतिशत महिलाओं से पिछले 12 महीनों में दो बार रिश्वत मांगी गई। *(न.दु., 08.03.14)*

राज्य में लोकायुक्त को ताकतवर बनाने की तैयारी

ऐसे होगी शिकायत

लोक सेवक के पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार व काम न करने के बारे में लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती है। इसके लिए शिकायत कर्ता को शिकायत के साथ सिर्फ शपथ-पत्र देने की जरूरत होती है।

लोकपाल कानून के लागू होने के साथ ही प्रदेश में भी लोकायुक्त को ताकतवर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लोकायुक्त कार्यालय ने 41 साल पुराने कानून को बदलने के लिए नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसे अब राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भिजवाया गया है। कार्मिक विभाग इस पर विचार कर रहा है। अगर इसे लागू किया जाता है तो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों सहित कानून के तहत बनी कंपनियां, निगम, समितियां और ट्रस्ट भी लोकायुक्त के दायरे में आ जाएंगे।

लोकायुक्त की सिफारिश नहीं मानने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी नए कानूनों में किया गया है। इसी तरह लोकायुक्त के निर्देश पर छापा मारने, भ्रष्टाचार से जमा की गई सम्पत्ति को अस्थाई तौर पर जप्त करने, प्रारंभिक जांच पूरी करने को अधिकतम 90 दिन की मियाद तय करने जैसे अधिकार लोकायुक्त को दिए जाने की मांग की गई है। लोकपाल कानून का हवाला देकर लोकायुक्त कानून में बदलाव के इन सुझावों को जल्द ही उच्च स्तर पर विचारार्थ भिजवाया जाएगा। *(रा.प., 28.01.14)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
पाली	रतनलाल मेघवाल	ब्लाक प्रा.शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति,रायपुर	10,000	दै.भा., *01.01.14*
बीकानेर	महेश आचार्य	लिपिक, नगर निगम, बीकानेर	1,500	रा.प., *03.01.14*
अजमेर	मनीष सांगेला	कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, ब्यावर, अजमेर	10,000	दै.भा., *07.01.14*
जोधपुर	डॉ. सुरेन्द्र जैन	ब्लॉक सीएमओ, रेवदर (सिरोही)	3,000	दै.भा., *09.01.14*
उदयपुर	लक्ष्मणराय लीलानी	सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम, बड़गांव	3,50,000	रा.प. एवं दै.भा., *12.01.14*
झालावाड़	बृजमोहन देवराज	कोतवाल, कोतवाली, झालावाड़	40,000	दै.भा. एवं रा.प., *13.01.14*
सीकर	रिचा वर्मा बजरंग लाल	कनिष्ठ अभियंता, विद्युत निगम, सीकर हैल्पर, विद्युत निगम सीकर	4,000	रा.प., *28.01.14*
जयपुर	सुरज्ञान सिंह गुर्जर	एएसआई, थाना खो नागोरियान, जयपुर	5,000	रा.प एवं दै.भा., *29.01.14*
जालौर	रतन सिंह चारण	बाबू, नगर परिषद, जालौर	3,000	दै.भा., *29.01.14*
जोधपुर	संजय कुमार मंगल	एईएन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम	40,000	दै.भा.एवं रा.प., *31.01.14*
भीलवाड़ा	प्रभु दयाल बेनीवाल	अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भीलवाड़ा रेंज	30,000	रा.प., *01.02.14*
भरतपुर	यदुवीर सिंह	कांस्टेबल, खेड़लीमोड़ पुलिस चौकी, भरतपुर	1,500	दै.भा.एवं रा.प., *05.02.14*
जयपुर	हरि सिंह	हेड कांस्टेबल, भांकरोटा थाना, जयपुर	15,000	दै.भा., *05.02.14*
जालौर	दीपक गुप्ता	एक्सईएन, नगर परिषद, जालौर	20.000	दै.भा., *07.02.14*
भरतपुर	गिर्राज सिंह	प्रभारी एएसआई, नगर थाना, जालूकी पुलिस चौकी	8,000	रा.प., *08.02.14*
राजसमंद	बन्ने सिंह मीणा	एईएन, पीएचईडी कार्यालय, नाथद्वारा	25,000	दै.भा., *18.02.14*
जयपुर	अनंत कुमार सिन्हा	मुख्य प्रबंधक, प्रधान कार्यालय एस.बी.बी.जे. बैंक	30,000	दै.भा., *01.03.14*
नागौर	नरेशकुमार रावता राम सलीम तगाला	थानेदार, लाडनूं थाना, नागौर एएसआई, लाडनूं थाना, नागौर थानेदार का दोस्त और बिचौलिया	2,00,000	दै.भा., *04.03.14*
जयपुर	गुलाब चन्द	वरिष्ठ लिपिक, विद्युत वितरण निगम, झोटवाड़ा	10,000	दै.भा., *06.03.14*
भीलवाड़ा	दया शंकर गुप्ता	जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन कार्यालय	5,000	रा.प., *15.03.14*
श्रीगंगानगर	पी.सी.यादव	केन्द्राधीक्षक, राजकीय आरटीआई, श्रीकरणपुर	15,000	रा.प., *28.03.14*

खाद, बीज पर सरकार रखेगी नजर

प्रदेश में अब कृषि के लिए उपयोग में आने वाले बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं पर राज्य सरकार पूरी नजर रखेगी। इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर पर और जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया है। सरकार ने बाजार में घटिया व कम तोल के बीज किसानों को मिलने की शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इन सतर्कता समितियों को किसी भी बीज, उर्वरक और कीटनाशक उत्पाद निर्माता कंपनियों की जांच करने का अधिकार होगा।

कृषि विभाग ने बीज, उर्वरक और कीटनाशक उत्पादों पर नजर रखने के लिए तीन राज्य स्तरीय समितियां बनाई हैं। प्रत्येक समिति में कृषि और उससे जुड़े विभागों के पांच-पांच सदस्य होंगे।

(रा.प., 14.03.14)

प्रदेश में बना गो सेवा निदेशालय

प्रदेश में गो सेवा निदेशालय का गठन किया गया है। भाजपा के घोषणा-पत्र में यह वादा किया गया था। सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे पूरा किया है। निदेशालय के अधीन होने वाले कार्यों की रूपरेखा बनाने का काम भी शुरू हो गया है।

गो सेवा आयोग और प्रदेश में संचालित डेयरियां अब निदेशालय के अधीन होंगी। निदेशालय देशी नस्लों के संरक्षण, संवर्धन और नस्ल सुधार के साथ-साथ पशु प्रजनन नीति के अनुसार विदेशी नस्ल के संकरीकरण को प्रोत्साहित करेगा। चरागाहों और गोशालाओं की भूमियों को चिन्हित कर चरागाह विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। गो तस्करी रोकने के लिए कानून भी बनाए जाएंगे। *(रा.प., 03.03.14)*

तय की ग्रामीण विकास प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पंचायत राज विभाग की बैठक में गांवों के विकास के लिए पांच प्राथमिकताएं तय की है। इन प्राथमिकताओं में स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण, जल निकासी के साथ सड़क, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, ऊर्जा एवं आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि को शामिल किया गया है।

बैठक में विभाग की 60 दिन की कार्ययोजना और आगामी पांच साल के लिए तय किए जाने वाले लक्ष्यों पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने मिड-डे मील की गुणवत्ता व वितरण व्यवस्था में सुधार लाने पर खास ध्यान देने की आवश्यकता जताई। *(रा.प., 05.01.14)*

बन्द नहीं होंगी कोई भी योजनाएं

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साफ किया है कि पिछली सरकार की योजनाओं को बन्द करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी सरकार इन योजनाओं की निरंतर समीक्षा कर इनमें आवश्यक सुधार करेगी, ताकि योजनाओं का जनता को भरपूर लाभ मिल सके, जो पिछली सरकार में बेहतर क्रियान्विति के अभाव में नहीं हो सका।

मिडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए हमने कभी नहीं कहा कि उनकी योजनाओं को बन्द किया जाएगा। सरकार भले ही बदल जाती है लेकिन उसकी प्रक्रिया बंद नहीं की जाती। हमने योजनाओं में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। *(रा.प., 15.02.14)*

पेंशन का हो नियमित भुगतान

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्वीकृत पेंशन धारियों को पेंशन का भुगतान नियमित रूप से किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। पेंशन भुगतान के लिए सभी जिलों में जरूरत के मुताबिक बजट भी आवंटित किया जा चुका है।

जिला कलेक्टरों को डाक विभाग के स्तर पर हो रही देरी से निपटने के लिए निरीक्षण व्यवस्था को मजबूत करने को कहा गया है। पेंशन महाअभियान की अवधि में 30 लाख 47 हजार पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत हुई थी। वर्तमान में विभिन्न योजनाओं में पेंशनधारकों की संख्या करीब 56 लाख हो गई है। *(दै.भा., 14.02.14)*

उम्र 60 साल तो मिलेगा मुफ्त इलाज

सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सरकारी इलाज व जांचों की सुविधा अब 60 साल या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क मिल सकेगी। पहले 65 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को ही यह सुविधा मिलती थी। सरकार की ओर से संचालित अस्पतालों में उन्हें मुफ्त दवा व जांच की सुविधा मिलेगी। सरकार की ओर से इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

सरकार के इस निर्णय से उन लाखों बुजुर्गों को राहत मिलेगी जिनको उम्र की वजह से इलाज कराने में दिक्कत आती थी। गौरतलब यह है कि 65 साल की उम्र में निःशुल्क इलाज की योजना भी भाजपा के शासनकाल से ही चली आ रही है। *(दै.भा., 26.01.14)*

आदिवासी जिलों में मिलेगी नौकरी

राज्य में आदिवासी बहुल जिलों में नौकरी लगने पर अब वहां नौकरी करनी ही होगी। किसी भी तरह का जुगाड़ लगा कर दूसरे जिले में तबादला संभव नहीं होगा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में 23 तहसीलों को मिलाकर एक विशेष अनुसूचित क्षेत्र बनाया हुआ है। यहां के लिए सरकार अलग सेवा नियम बना रही है।

इन जिलों में आपस में ही तबादले हो सकेंगे। इसके लिए कार्मिक विभाग अधीनस्थ सेवाओं से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने में जुटा है। राज्य सेवा में चयनित अधिकारियों का तबादला दूसरे जिलों में भी किया जा सकेगा। लेकिन अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों का इन जिलों के लिए अलग से चयन किया जाएगा और उनकी सेवाएं इन्हीं जिलों में होंगी।

(रा.प., 11.02.14)

पंचायत समितियों तक पहुंची सरकार

राज्य सरकार ने 10 दिनों तक भरतपुर संभाग में अपना आसन जमाया। मंत्रियों ने संभाग के चारों जिलों भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों का सघन दौरा किया। वे शहरों, कस्बों और गांवों की वास्तविक स्थिति से रूबरू हुए। उनके सामने बिजली चोरी, अप्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ, चिकित्सा उपकरणों की कमी, स्कूलों की दुर्दशा व खराब पोषाहार जैसी कई समस्याएं सामने आई।

गांव-गांव में जनसुनवाई की गई। निरीक्षण के दौरान जहां कहीं गड़बड़ियां सामने आई वहां जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। लोगों की शिकायतों का समाधान भी किया गया।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्वयं मौजूद रह कर सभी स्थितियों का अवलोकन किया और समस्याओं के निराकरण व क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रियों व अधिकारियों को निर्देश दिए। परिणाम स्वरूप संभागीय स्तर पर विकास योजनाएं बनने का सिलसिला शुरू हुआ है। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जगा है।

(रा.प., 11.02.14)

बिजली कंपनी देगी मुआवजा

विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉमेंस तय किए हैं। इसमें उपभोक्ता सेवाओं के निस्तारण संबंधी नियम-कायदे तय कर दिए गए हैं। इसमें उपभोक्ता बिजली कंपनियों को सप्लाई बहाल करने सहित अन्य शिकायतों में से 90 फीसदी राहत देनी होगी। इसके साथ ही बिजली सप्लाई करने का समय भी तय किया गया है। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उपभोक्ता को बिजली कंपनी की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है।

आरईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों को नया कनेक्शन देने, जला हुआ ट्रांसफॉर्मर बदलने, बिजली बिल की शिकायत, हाईवोल्टेज करंट, मीटर बदलना, डिमांड नोटिस, सहित अन्य शिकायतों के समय पर निस्तारण करने के लिए कहा है। यदि इन शिकायतों का तय समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो बिजली वितरण कंपनियों को उपभोक्ता को मुआवजा देना होगा।

(दै.भा.एवं न.नु., 25.02.14)

बिजली कंपनियों की होगी ऑडिट

ऊर्जा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बिजली कंपनियों के घाटे पर चिन्ता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में बिजली कंपनियों का घाटा 15 हजार करोड़ रुपए था। अब यह 70 हजार करोड़ रुपए को पार कर गया है। उन्होंने इसके लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बिजली कंपनियों की ऑडिट कराई जाएगी। यह ऑडिट केन्द्र सरकार की एक एजेंसी से करवाया जाएगा।

राज्य सरकार ने इसके लिए एजेंसी से बात कर ली है। ऑडिट एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्र में होगी। ऑडिट के परिणामों की ऊर्जा विभाग के स्तर पर समीक्षा की जाएगी और उचित पाए जाने पर पूरे राज्य में ऑडिट कराएगी।

(रा.प., 04.01.14, 31.01.14)

धड़ल्ले से हो रहे अवैध कनेक्शन

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां जहां करोड़ों रुपए के घाटे से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दबाव के चलते बिजली चोरी करने वालों की पौ-बारह है। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में हालात यह है कि अवैध ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोर धड़ल्ले से खेती का काम कर रहे हैं।

जयपुर ग्रामीण सर्किल में राजस्व वसूली के लिए जब जांच टीम फील्ड में उतरी तो टीम को ऐसे तीन ट्रांसफारमर अवैध मिले, जिन्हें जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरी का हमेशा ही बोलबाला रहा है। ट्रांसफारमर से लेकर विद्युत तार चोरी के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ताजा मामलों में चोरों ने अवैध ट्रांसफारमर से कनेक्शन शुरू कर दिया।

(रा.प., 10.03.14)

सुधरेगा बिजली सिस्टम

प्रदेश में उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने और 24 घंटे घरेलू तथा आठ घंटे कृषि कनेक्शनों को बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बिजली वितरण कंपनियां रोडमैप बना कर काम करेंगी। इसके लिए इंजीनियर पहले मौजूदा सिस्टम की खामियों का सर्वे करेंगे। इसके बाद सिस्टम में सुधार के लिए रोडमैप बना कर काम होगा साथ ही अधिकारियों व इंजीनियरों की जिम्मेदारी भी तय होगी।

बिजली सिस्टम की मौजूदा स्थिति तथा सुधार के लिए जयपुर में आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ऊर्जा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने तीनों बिजली कंपनियों के एक्सईएन और उच्च अधिकारियों से बिजली सिस्टम की वर्तमान खामियों और सुधार के लिए फीडबैक लिया। उन्होंने आला अधिकारियों और इंजीनियरों को सुधार के लिए टीमवर्क से काम करने को कहा, जिससे जल्द ही बिजली सप्लाई और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हो सके।

(दै.भा., 02.03.14)

आंतरिक अंकेक्षण में लेटलतीफी क्यों?

राज्य सरकार बिजली छीजत की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तरफ जहां एनर्जी ऑडिट करवा रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों के दफ्तरों के हिसाब-किताब की जांच राम भरोसे है। अकेले जयपुर डिस्कॉम के 189 उपखण्ड कार्यालयों में से अधिकांश में पिछले तीन साल से आंतरिक अंकेक्षण का काम लम्बित चल रहा है।

इनमें से भी कई दफ्तर तो ऐसे हैं जहां पांच साल से हिसाब-किताब की जांच नहीं हुई। ऑडिट की धीमी रफ्तार के चलते गबन के कई मामले प्रकाश में आने के बावजूद भी डिस्कॉम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अधिकारी सिर्फ स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए खुद का बचाव करने में लगे हैं।

(रा.प., 07.02.14)

वित्तीय प्रबंधन में होगा सुधार

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां अब अपने वित्तीय प्रबंधन में सुधार कर करोड़ों रुपए के बढ़ते घाटे को कम करेंगी। इसके लिए डिस्कॉम के चेयरमैन आर.जी.गुप्ता ने जयपुर डिस्कॉम के डायरेक्टर (फाइनेंस) दीपक श्रीवास्तव को जिम्मेदारी देते हुए सभी वित्तीय मामलों की पुनरीक्षा एवं सुझावों के लिए नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि तीनों बिजली वितरण कंपनियों में वित्तीय मामलों में सुधार हो तथा नई व्यवस्था लागू की जा सके।

वित्तीय सुधार को लागू करते हुए जयपुर डिस्कॉम के डायरेक्टर (फाइनेंस) ने भी सभी अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन की सुदृढ़ता पर विशेष जोर देने को कहा और इसके लिए निर्देश भी जारी किए। सभी अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करना जरूरी किया गया है। श्रीवास्तव का कहना है कि वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ता से लागू करने के लिए सख्ती की जा रही है, इससे सेवाओं में सुधार होगा और बिजली कंपनियों की हालत सुधरेगी। *(दै.भा., 16.02.14)*

बिजली उत्पादन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड

राजस्थान परमाणु बिजलीघर की पांचवी इकाई ने 530 दिनों तक निरंतर उत्पादन कर रिकॉर्ड कायम किया है। यह इकाई दाबित भारी पानी रिएक्टरों के सर्वश्रेष्ठ समूह में शामिल हो गई है।

केन्द्र निदेशक विनोद कुमार व मुख्य अधीक्षक जेआर देशपांडे ने बताया, 2 अगस्त 2012 को एक बजकर 56 मिनट पर ग्रिड से इस इकाई को सिंक्रोनाइज किया गया था। 14 जनवरी को दोपहर एक बजकर 56 मिनट पर पूर्ण क्षमता का उत्पादन करते हुए 530 दिनों की अवधि को पूरा किया। 530 दिन प्रचालन अवधि में कोई अग्नि और औद्योगिक दुर्घटना भी नहीं हुई, जो एक कीर्तिमान है। *(रा.प., 15.01.14)*

रोजाना होता है 10 लाख लीटर पानी चोरी

राजधानी में रोजाना 10 लाख लीटर पीने का पानी अवैध कनेक्शनधारी मुफ्त में गटक जाते हैं। जलदाय विभाग का खुद का मानना है कि यहां ऐसे करीब 25 हजार कनेक्शन हैं। यही वजह है कि नियमित उपभोक्ताओं को नियमों के मुताबिक पूरा पानी नहीं मिल पाता। अवैध कनेक्शनों के मामले में विभाग के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं। इसके बावजूद आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई। राजधानी में परकोटा और कच्ची बस्तियों में सरकारी पेयजल की लाइन से अवैध कनेक्शन लेने वालों की संख्या ज्यादा है।

हाल ही हुई जलदाय विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अवैध कनेक्शनधारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और शहर के नियमित प्रत्येक उपभोक्ता को नियमों के अनुसार पीने का पानी देने को कहा था। *(रा.प., 04.01.14)*

विजिलेंस विंग बने तो रुके पानी चोरी

सरकारी पेयजल की लाइन से अवैध कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में अभी जलदाय विभाग असहाय नजर आ रहा है। विभाग का कहना है कि विजिलेंस विंग के गठन होने के बाद ही इन पर नकेल लग पाएगी।

सूत्रों के मुताबिक विभाग ने विजिलेंस विंग गठन का प्रस्ताव करीब दो माह पहले ही शासन सचिवालय में भेज दिया था। इस विंग के पदों पर नियुक्ति के मामले में विभाग के अधिकारियों की डीपीसी भी हो चुकी है। लेकिन शासन सचिवालय की ओर से हरी झंडी नहीं मिलने से विजिलेंस विंग के गठन का मामला अभी अधर में है। राजधानी में ही विभाग ने अवैध कनेक्शन लेने वाले पच्चीस हजार लोगों को चिन्हित कर रखा है। अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जलदाय विभाग ने सभी जिलों में विजिलेंस विंग के गठन का प्रस्ताव बनाया है। प्रमुख शासन सचिव प्रेम सिंह मेहरा का कहना है कि शीघ्र ही विजिलेंस विंग का गठन होगा। *(रा.प., 22.01.14)*

स्कूल कॉलेजों में हो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

जल की बचत एवं संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों, कॉलेजों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। पीएचईडी और अन्य संबंधित विभागों को इसके लिए गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल संरक्षण व जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन जिला स्तरीय कार्यशाला में जयपुर कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने अपने यह विचार व्यक्त करते हुए जिला प्रमुख से आग्रह किया कि वे पंचायतीराज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जल का सदुपयोग व बचत करने के लिए प्रेरित करने के सार्थक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम दस-दस लीटर पानी की बचत का संकल्प लें। जिला प्रमुख हजारीलाल नागर ने कहा कि नागरिकों को पानी का मितव्यतता से उपयोग करना चाहिए। *(दै.भा., 26.02.14)*

जल सृष्टि का आधार-कोठारी

पूरी सृष्टि जल पर आधारित है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। पृथ्वी, चन्द्रमा, अंतरिक्ष और सूर्य की किरणों की झिलमिल में भी जल मिलेगा। हम जल के कणों से बाहर नहीं हैं, एक-दूसरे से इनके माध्यम से ही जुड़ें हैं। यह कहना है पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का। जयपुर में किशनपोल बाजार स्थित आरोग्य भारती संस्थान द्वारा आयोजित समारोह में 'जल ही जीवन है' विषय पर व्याख्यान में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने चिंता जताई कि आज सभी सुविधाभोगी होते जा रहे हैं और प्राकृतिक जल से दूरी बना ली है। नलों के पानी में जो ऊर्जा है उसमें डेसिटी कम होती है, जो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण चेतना और स्मृति लुप्त होती जाती है। जबकि प्राकृतिक जल में डेसिटी ज्यादा होती है और वह कोशिकाओं की चेतना तक पहुंच जाती है। *(रा.प., 04.01.14)*

भारत हो सकता है जल संकट वाला देश

भारत 2020 तक जल की कमी वाला देश बन सकता है। इससे उद्योग जगत के लिए जल संकट पैदा होगा और उद्योग पर जल संरक्षण के लिए दबाव बढ़ेगा। वैश्विक गैर सरकारी संगठन सीडीपी के 'द बिजनेस केस फॉर वाटर डिसक्लोजर इन इंडिया' शीर्षक से जारी अध्ययन में यह बात कही गई है।

अध्ययन के अनुसार करीब 50 फीसदी गांवों में संरक्षित पेयजल का स्त्रोत नहीं है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण, कृषि तथा शहरीकरण के विस्तार से जल संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धी मांग बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार 'वाटर रिसोर्स ग्रुप इंडिया' के हवाले से कहा गया है कि भारत को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है जहां 2030 तक मांग, आपूर्ति के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक हो जाएगी। इसलिए सरकार को जल संरक्षण के लिए उद्योगों के लिए नीति बनानी होगी। *(न.दु., 19.03.14)*

भूजल स्तर बढ़ाने की कवायद

बारिश के बाद प्रदेश के राजमार्गों के किनारे बहते हुए जल को अब एकत्र किया जा सकेगा। अब इस पानी की दिशा कुएं और बावड़ियों तक तय की जाएगी ताकि यह पानी लम्बे समय तक काम आ सके। भूजल विभाग इसके लिए कवायद शुरू करने की योजना बना रहा है।

जानकारी के अनुसार भूजल विभाग ने यूरोपियन स्टेट पार्टनरशिप पायलट प्रोजेक्ट के तहत भूजल स्तर बढ़ाने की पहल की है। जिसमें हाईवे के दोनों ओर पांच-पांच सौ मीटर के दायरे में बने तालाबों और बावड़ियों में जमा पानी का उपयोग भूजल स्तर बढ़ाने में किया जाना है। विभाग ने इसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पूरे प्रदेश में भूजल रिचार्ज की यह योजना लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। *(रा.प., 27.02.14)*

हरियाणा कर रहा है पानी की चोरी

जल संसाधन विभाग की इंदिरा गांधी नहर से पानी माफिया पानी चुरा कर हरियाणा स्थित गांवों और कस्बों को सप्लाई कर रहा है। नहर से पानी चुराने के मामले में बिरानी और भादरा सबसे अव्वल है। दोनों कस्बों में सक्रिय पानी माफिया ने आईजीएनपी से पानी चुरा कर हरियाणा के काश्तकारों को बेचने का धंधा चला रखा है।

पानी माफिया ने नहर पर पंपसैट लगाने के साथ-साथ खुद की पाइप लाइन तक डाल ली है, जिसके जरिए चोरी का पानी हरियाणा तक पहुंचाया जा रहा है। पानी माफिया करीब 50 क्यूसेक पानी प्रतिदिन नहर से चुरा रहे हैं। पानी माफिया के बढ़ते दायरे के कारण नहर के आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। *(रा.प., 31.01.14)*

महिलाएं बनेंगी कारीगर

महिलाएं भी सरकारी योजनाओं में निर्माण का काम करेंगी। बूंदी में निर्मल भारत अभियान योजना के तहत महिलाओं से शौचालय बनवाए जाएंगे। यह कार्यक्रम मनरेगा योजना के तहत चलेगा। पहले चरण में हर ब्लॉक से 50 महिलाओं का चयन किया गया है। इन महिलाओं को मिस्त्री के काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुशल महिला कारीगर को 350 रुपए व अकुशल मजदूर को 133 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे।

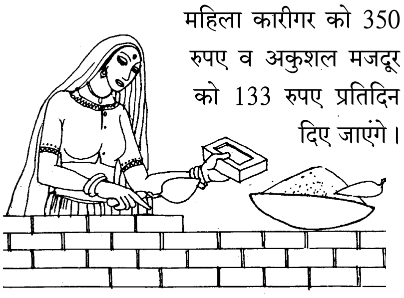

बूंदी कलेक्टर आनंदी के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह पहल की गई है। महिला मिस्त्री इस काम को स्थायी रोजगार का जरिया भी बना सकेंगी। *(दै.भा., 17.02.14)*

स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर छह हस्तियों को स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। ये हस्तियां ऐसी है जो सुर्खियों में नहीं रह कर महिला सशक्तिकरण और उनकी जागरूकता के लिए काम कर रही हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अयोजित कार्यक्रम में डॉ. वर्तिका नंदा को रानी गाइदिनलियु जेलियांग पुरस्कार, मानसी प्रधान को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, डॉ. एम वैकेया को रानी रूद्रम्मा देवी पुरस्कार, बीना सेठ लश्करी को माता जीजा बाई पुरस्कार, राधा प्रसंथी को कन्नागी पुरस्कार और डॉ.सीमा साखरे को देवी अहिल्या बाई होलकर पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कहा कि अकेले कानून बनाने से हम महिलाओं को सशक्त नहीं कर पाएंगे। कानून को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए तंत्र विकसित करना होगा। हमें अपनी मानसिकता और सामाजिक दायरे में अपने व्यवहार में भी बुनियादी बदलाव करने होंगे।

(दै.भा., 09.03.14)

महिला आरक्षण में पुरुष बाधक

राज्यपाल मार्ग्रेट आल्वा का मानना है कि राजनीति में महिलाओं के आरक्षण में रुकावट के लिए राजनीतिक दल नहीं, बल्कि पुरुष नेता सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। राजनीति में पुरुष अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। फिर भी चूंकि राज्य सभा में बिल आ गया है, इससे उम्मीद बंधी है। महिला दिवस पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ज्यादा महिलाएं चुनाव में जीत कर आएंगी।

प्रदेश की महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह महिलाओं और पुरुषों के लिए उत्सव का दिन है। महिलाओं ने अब तक कई संघर्ष किए हैं और संतोष की बात यह है कि अब लोगों की सोच बदल रही है। वह महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने में आगे आने लगे हैं। *(रा.प., 09.03.14)*

प्रदेश में मातृ-मृत्यु दर में गिरावट

प्रदेश पर लगा मातृ-मृत्यु दर अधिक होने का दाग अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। हाल ही जारी हैल्थ सर्वे 2012-13 की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। पहले राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं में से 331 की मौत हो जाती थी, वहीं अब यह आंकड़ा गिरकर 208 रह गया है।

चिकित्सा विभाग को पिछले दिनों वार्षिक हैल्थ सर्वे 2012-13 की द्वितीय अपडेट रिपोर्ट मिली है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में मातृ-मृत्यु दर रोकने में राजस्थान सफल रहा है। इसके पीछे जननी शिशु सुरक्षा योजना का असर बताया जा रहा है, वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बढ़ी प्रसव सुविधाओं से भी मातृ-मृत्यु दर में कमी आई है। *(रा.प., 20.03.14)*

बालिकाओं में हो नेतृत्व क्षमता

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए संचालित सभी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाकर क्रियान्वित करना होगा। बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास होना आवश्यक है। बालक-बालिकाओं की शिक्षा में व्याप्त अंतर को खत्म कर राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सकता है।

बालिका दिवस पर सर्व शिक्षा अभियान की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय सम्मेलन में यह विचार शिक्षामंत्री कालीचरण सराफ ने व्यक्त करते हुए कहा कि बालिकाओं के नामांकन व ठहराव बढ़ाने, उनके आत्मविश्वास व मनोबल में वृद्धि आदि के लिए इस तरह के सम्मेलन होने चाहिए। ऐसे सम्मेलन केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि जिला व उपखण्ड स्तर पर भी होने चाहिए।

उन्होंने इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा लगाई गई स्टाल्स और किशोरी बाल मेले का अवलोकन किया। इनमें बालिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतिविधियों, क्रियाकलापों की उन्होंने प्रशंसा की और बालिका शिक्षा के ब्रोशर का भी विमोचन किया। *(दै.भा., 25.01.14)*

भ्रूणहत्या: एनजीओ करेंगे जागरूक

प्रदेश में अब नई स्कीम के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए स्वयंसेवी संगठनों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जिन जिलों में मातृ-मृत्यु दर अधिक है, गिरता लिंगानुपात और अधिक संख्या में सोनोग्राफी सेंटर काम कर रहे हैं, वहां पर एनजीओ का चयन किया जाएगा।

पीसीपीएनडीटी सेल के स्टेट नोडल अधिकारी किशनाराम ईशरवाल नें बताया कि सभी प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा जा चुका है। वर्तमान में राजस्थान में 342 एनजीओ कार्यरत हैं। पहले एनजीओ को किसी तरह का फंड नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जिले में चयनित एनजीओ को धन मुहैया कराया जाएगा।

(दै.भा., 10.02.14)

स्वयं सहायता समूहों को सहायता

लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को लुभाने की कवायद के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को अर्थात एसएचओ द्वारा ली गई उधार पर 1400 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने की घोषणा की है। केन्द्र की महात्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को यह ब्याज सहायता प्रदान की गई है।

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह सहायता उन महिला एसएचजी को मिलेगी जिन्होंने एक अप्रेल, 2013 से कर्ज लिया है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख से सभी बैंक 150 चुने हुए पिछड़े जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को तीन लाख रुपए तक का कर्ज 7 फीसदी ब्याज दर पर देंगे। समय पर कर्ज चुकाने पर इन समूहों को तीन फीसदी की और ब्याज सहायता मिलेगी। इससे प्रभावी ब्याज दर चार फीसदी ही रह जाएगी।

(न.दु., 04.02.14)

निवेशक शिक्षा

जरूरी है निवेशकों का संरक्षण: सिन्हा

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष यू.के.सिन्हा ने कहा है कि क्षेत्रीय शेयर बाजारों को सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। अब बदलाव के दौर में रीजनल एक्सचेंजों का अस्तित्व सिमट कर रह गया है। ऐसे में निवेशकों के संरक्षण और उनमें निवेश के प्रति जागरूकता लाने के लिए नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

जयपुर में पीएचडी चैम्बर की ओर से आयोजित निवेशक संरक्षण और शिक्षा के नए प्रयास विषयक सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब कंपनियों की क्षेत्रीय शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य हुआ करती थी, लेकिन इस नियम को खत्म हुए ही एक दशक से अधिक समय बीत गया। अब ऐसे एक्सचेंजों के पास अपनी स्वयं की लिस्टिंग कंपनियां ही नहीं रही तो उनका कारोबार घाटे का सौदा हो गया है।

निवेशक जागरूकता के बारे में उन्होंने कहा कि हमने डेढ़ साल पहले चौबीस घंटे का काल सेंटर स्थापित किया था, जिसमें देशभर से दो लाख से भी ज्यादा कॉल मिली, जबकि राजस्थान से सिर्फ 1000 ऐसी कॉल दर्ज की गई, निवेशक जागरूकता के मामले में राजस्थान पिछड़ा है।

राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के मानद महासचिव और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के संस्थापक डॉ.के.एल. जैन ने कहा कि कंपनियों की धोखाधड़ी से परेशान निवेशकों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी होना चाहिए। इस अवसर पर सेबी और कंपनी मामलों के विभाग की ओर से चलाए जा रहे निवेशक संरक्षण और शिक्षा विषयक पैनल डिस्कशन का भी आयोजन किया गया। इसमें पीएचडी चैंबर की केपिटल मार्केट समिति के चेयरमेन पृथ्वी हल्दिया, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के चेयरमेन ओ.पी.अग्रवाल, कट्स इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल प्रदीप एस महता, ग्लोबल इन्वेस्टर के दीपक श्रीवास्तव, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के एम.डी.पवन कुमार विजय और बीएसई लि. के नेहल वोरा ने अपने विचार रखे। *(दै.भा. एवं रा.प., 07.01.14)*

पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा होगी प्रभावित

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ते रहने से उच्च स्तर की वार्मिंग भारत की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। दरअसल, एक वैश्विक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इसका देश के चावल और मक्का उत्पादन पर कहीं अधिक गंभीर असर पड़ सकता है।

जापान के याकोहामा में जारी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अर्थात आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फसल की तरह देश में मत्स्यपालन उद्योग पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन को अक्सर ओजोन के साथ जोड़कर देखा जाता है। जिसने क्षोभमंडलीय ओजोन में वृद्धि की है। इससे फसल की पैदावार को नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व औधोगिक काल से ओजोन की मात्रा में वृद्धि ने संभवतः मुख्य फसलों के वैश्विक उत्पादन को प्रभावित किया है। गेहूं, सोयाबीन, मक्का और चावल के उत्पादन को नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। *(न.नु., 31.03.14, 01.04.14)*

वित्तीय सेवाएं

बैंकों की सर्विस चार्ज बढ़ाने की तैयारी

एक अप्रेल से आपकी बचत पर एक और मार पड़ने वाली है। बैंकों ने सेवाओं के बदले ली जाने वाली सर्विस चार्ज में 10 से 50 फीसदी तक बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। बैंक आम खाताधारकों पर अभी 12 सेवाओं पर प्रति तिमाही 200 से 300 रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि जयपुर में दस हजार से अधिक चालू और बचत खाते ऐसे हैं जिन पर तीन महीने में ही 1000 से 1500 रुपए सेवा शुल्क के रूप में कट जाते हैं।

बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक्सपर्टस का कहना है कि सेवा शुल्क कम से कम 10 से 50 फीसदी तक ही बढ़ सकता है। बहरहाल, यह फैसला बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को करना है। एसबीआई, एसबीबीजे, बैंक आफ बड़ौदा व आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधकों का कहना है कि एक तिमाही में कम से कम 200 से 300 रुपए या इससे अधिक राशि सुविधा शुल्क खाते से काटी जा रही है। *(दै.भा., 21.03.14)*

सड़क सुरक्षा

सड़क नियामक का गठन शीघ्र

निजी क्षेत्र की सड़क निर्माण क्षेत्र में रुचि घट रही है और सरकार को अधिक सड़क परियोजनाओं का आंवटन अपने स्तर पर ही करना पड़ रहा है। क्योंकि, निजी क्षेत्र को गत वर्षों के दौरान भूमि अधिग्रहण में वनीय एवं पर्यावरण स्वीकृति जैसी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। इसके कारण अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हुआ है। बैंक ऋण साख गैर निष्पादित सम्पत्ति में परिवर्तित हो गई।

अब सरकार ने सड़क नियामक के गठन का निर्णय लिया है। इस आशय का प्रस्ताव सड़क परिवहन मंत्रालय के समक्ष रखा जा सकता है। नियामक के गठन के बाद इसमें संबंधित सभी विवादों को नियामक के स्तर पर ही सुलझाया जा सकेगा। भारतीय राजमार्ग नियामक प्राधिकरण विधेयक-2013 पर विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिक्रिया मांगी गई है। माना जा रहा है कि मंत्रालय जल्द ही इस पर कोई निर्णय ले सकता है। सड़क नियामक स्थापित करने का मुद्दा गत 10 माह से लम्बित चल रहा है। केन्द्रीय मंत्री आस्कर फर्नाडीस ने कहा है कि इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद एक कार्यकारी आदेश के द्वारा नियामक की नियुक्ति की जाएगी। संसद में इसे पारित करने में समय लग सकता है। इस कारण सरकार कार्यकारी आदेश का सहारा ले सकती है। अधिकारियों का कहना है कि नियामक के अस्तित्व के बाद 2000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं पर पुनः कार्य शुरू हो जाने की संभावना है। *(न.नु.11.01.14)*

जन स्वास्थ्य

बनेगा स्वास्थ्य नियामक आयोग

प्रदेश में तमाम सरकारी व निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य नियामक आयोग बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अस्पतालों में मौजूद सुविधाओं और हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अस्पतालों में मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत होने पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।

आयोग अस्पतालों को सुविधाओं के आधार पर ग्रेडिंग भी देगा, जिससे आमजन यह जान सकेगा कि कहां अच्छा इलाज संभव है। अच्छी ग्रेडिंग वाले अस्पतालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। *(दै.भा., 13.01.14)*

उपभोक्ता फैसले

महंगी पड़ी पिता के खाते से बेटे के लोन की वसूली

बेटे के लोन की वसूली के लिए वरिष्ठ नागरिक के पेंशन खाते से रुपए काटना स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की मानसरोवर शाखा को महंगा पड़ा। अब बैंक की मानसरोवर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक और मुख्य महाप्रबंधक को 28 हजार रुपए का हर्जाना देना होगा।

मामले के अनुसार शिप्रापथ निवासी देवकुमार सांघी का पेंशन खाता इस बैंक में खुला हुआ है। उनके बेटे अनुज सांघी ने इसी बैंक से लोन लिया था, जिसमें गारंटर देवकुमार बने थे। बैंक ने लोन अदायगी में देरी होने पर उनके पेंशन खाते से 37 हजार 500 रुपए काट लिए। बैंक से कारण पूछा तो बताया गया कि यह रुपए लोन अदायगी समायोजन के लिए काटे गए हैं। इस पर उन्होंने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत की। लोकपाल के आदेश पर बैंक को काटी गई यह रकम वापस उनके खाते में जमा करनी पड़ी।

देवकुमार ने एसबीबीजे बैंक के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराते हुए बताया कि वह एक बुजुर्ग व्यक्ति है। बैंक द्वारा उनके खाते से ऐसे समय पर गैरवाजिब तरीके से रुपए काटे गए, जब वह काफी बीमार थे। इससे उन्हें काफी मानसिक परेशानी हुई थी। मंच ने मामले की सुनवाई पर बैंक को सेवा का दोषी माना और 9 फीसदी की दर से ब्याज देने व 28 हजार रुपए हर्जाना भरने के आदेश दिए।

(रा.प., 14.02.14)

पार्किंग शुल्क ज्यादा वसूलना भारी पड़ा

जयपुर स्थित रामगंज बाजार निवासी रामजी लाल सोनी ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक और पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने अपने परिवाद में बताया कि वह 10 जून, 2012 को अपने रिश्तेदार से मिलने सिंधी कैंप बस

स्टैंड गया था। पार्किंग ठेकेदार ने उससे पार्किंग शुल्क 5 रुपए की जगह 10 रुपए मांगे। जब उन्होंने ज्यादा शुल्क वसूलने की शिकायत प्रबंधक से करने की बात की तो उसने उनकी व उनकी मां से बदसलूकी की। उन्होंने मजबूरन दस रुपए पार्किंग शुल्क दिया। इसकी शिकायत भी रोडवेज प्रशासन से की गई लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हारकर उन्होंने उपभोक्ता मंच का सहारा लिया।

मामले की सुनवाई में उपभोक्ता मंच ने इसे सेवा दोष माना। मंच ने रोडवेज के मुख्य प्रबंधक व पार्किंग ठेकेदार को आदेश दिए हैं कि वह ज्यादा वसूले 5 रुपए पर 10 जून, 2012 से बारह फीसदी ब्याज सहित उपभोक्ता रामजी लाल सोनी को वापस करे और साथ ही 6500 रुपए हर्जाना भी अदा करें।

(दै.भा., 15.03.14)

खास समाचार

फोन, मोबाइल या इंटरनेट ठप्प तो मिलेगा हर्जाना

अब टेलीफोन, मोबाइल या इंटरनेट सेवा में गड़बड़ी पर उपभोक्ता को सेवा प्रदाता कंपनी के अफसर का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। इनमें गड़बड़ी होने पर अब उपभोक्ता मंच में शिकायत की जा सकेगी और मंच उपभोक्ता को मानसिक परेशानी के बदले कंपनी से हर्जाना भी दिला सकेगा।

दरअसल, वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंचों से इन मामलों को सुनने का अधिकार छीन लिया गया था। लेकिन अब केन्द्रीय संचार मंत्रालय और केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात ने दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि इन मामलों की जिला उपभोक्ता मंच में भी सुनवाई हो सकेगी।

गौरतलब यह है कि 2009 के बाद से उपभोक्ता के पास सिर्फ दूरसंचार कंपनी के नोडल अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के पास ही अपनी शिकायत ले जाने का चारा बचा था। वहां समाधान नहीं होने पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) में मामला पहुंचता था। वह कंपनी पर जुर्माना भी लगाता था। उपभोक्ता की शिकायत तो दूर हो जाती थी, लेकिन उसे मानसिक परेशानी का कोई हर्जाना नहीं मिल पाता था।

ऐसे निकला रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को टेलीग्राफ अथॉरिटी मान उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नहीं माना, उसने उपभोक्ता और कंपनी के बीच मीडिएशन को ही सुलह का रास्ता माना। बाद में सभी कंपनी लाइसेंसी होने से उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में आ गई। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने इससे सभी उपभोक्ता मंचों को अवगत कराया है।

जैविक खेती को बढ़ावा

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की 58 प्रतिशत आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। जैविक खेती के प्रसार का सीधा संबंध उपभोक्ता सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। 'कट्स' द्वारा एस.एस.एन.सी., स्वीडन के आर्थिक सहयोग से राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दो वर्षीय परियोजना राजस्थान राज्य के छह सघन कृषि बहुल जिलों जयपुर, दौसा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कोटा में संचालित की जा रही है।

इस परियोजना के तहत जैविक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने, क्षमतावर्धन करने एवं जन पैरवी की गतिविधियों द्वारा आमजन को इसका महत्व बताने का प्रयास किया जाएगा। परियोजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों से किसानों में जैविक खेती के प्रति रूझान बढ़ेगा। इससे न केवल किसानों एवं उपभोक्ताओं को दीर्घकालीन लाभ होगा, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। परियोजना से प्राप्त सुझावों से सरकारी नीति-निर्माता एवं सम्बन्धित विभाग भी इस दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ा सकेंगे।

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, बी.एल.: बिजनेस लाइन

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।